*242. *[The questioner (Prof Sourendra BHattachargee) was absent. For answer, vide col.* 43-44 infra],

*243. *[The questioner (Shri Vishwasrao Ramrao Patil) was absent For answer,* vide *cols.* 44-45... infra].

Publication of Technical and Scientific Journals in Hindi

*244. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: †
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of research papers are being published in Japanese and Chinese in advanced areas of Science and Technology, Space, Electronics Biotechnology etc.;

(b) -whether there is any proposal for publishing research journals on Electronics and other areas in Hindi; and

(c) what is the scheme to promote research publications in Hindi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

The use of the Japanese and the Chinese languages for publications in adavnced areas of Sciene and Technology has been in vogue in Japan and China for a long time.

(b) and (c) The Government of India is encouraging publications of a high standard in Hindi on scienti fic and technical subjects including re-searh papers. The Department of Science and Technology has initiated a scheme of awards with cash prizes of Rs. 15,000/-, Rs. 10,000 [- and Rs 5,000]- annually as 1st, 2nd and 3rd prizes respectively, for publication of onginal books of high standard in Hindi in the following areas: Physics, Chemistry, Life Sciences and Engineering Sciences.

The examples of science periodicals! in Hindi are: 'MAUSAM' (published by the India Meteorological Department—abstracts of articles in Hindi) * 'PARMANU' (published by the Del partment of Atomic Energy); 'URJA BHARAT (pubished by the Department of Non-Conventional Energy Sources): 'ANTARIKSH BHARAT' (published by the Department of Space): 'SROTE' (published by the Department of Science and Technology): and 'PARYAVARAN' (published by the Ministry of Environment and Forests). The Department of Space also publishes Hindi books on various technical developments and projects such as SLV-3 launcher, and remote sensing.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, जिस आनन्द की अनुभूति संसद के किसी सदस्य को अपना प्रथम वक्तव्य देते हुए होती है वैसी ही अनुभूति मुझे अपना प्रथम तारांकित प्रश्न पूछते हुए हो रही है । सभापति जी, मेरी सदस्यता के एक साल पांच महीने और दो दिन के बाद मेरे किसी प्रश्न ने इन गुलाबी पन्नों के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया है । सभापति जी, मैं आनन्दातिरेक से भरते हुए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि अभी कल ही भारतीय भाषायें और कम्प्युटर विषय पर एक विशेष बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री जी की ओर से किया गया था । मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं उनके प्रति, क्योंकि संसद सदस्यों की बैठकें आयोजित किया जाना, उनसे सलाह मांगा जाना, यह तो संसदीय प्रणाली में आम बात है। लेकिन संसद में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर, सासदों की रुचि का आकलन करके उस विषय विशेष पर बैठक आयोजित करना

†The question was actually asked on the floor of the House by Smt. Sushma Swaraj.

और संसद के सत्र के चलते, स्वयं प्रधानमंत्री का उसकी अध्यक्षता करना यह अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहती हूं कि यह इनकी गंभीरता और इस विषय में उनकी रूचि का परिचायक है। इसलिये मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ यह प्रश्न पूछना चाहती हूं। मंत्री महोदया ने जवाब दिया है, उस में हिन्दी में शोध-पत्रिकाओं के प्रकाशन का क्या प्रस्ताव था, यह मेरा सवाल था। उसका सीधा जवाब हां या ना में दिया जा सकता था। लेकिन जवाब सीधा नहीं आया। मेरे सवाल का भाग (ख) यह था कि क्या इलेक्ट्रानिकी तथा अन्य क्षेत्रों में हिन्दी में शोध पत्रिकाएं प्रकाशित किए जाने का कोई प्रस्ताव है। इसका सीधा जवाब आ सकता था हां या नहीं। लेकिन जवाब घुमावदार ढंग से पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का दिया गया। सभापति जी आप जरा जवाब को देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए पुरस्कार का प्रावधान है पहला, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि दी जाती है। विज्ञान पत्रिकाओं के कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि पुस्तकों और पत्रिकाओं में फर्क है। पत्रिका और शोध पत्रिका में भी फर्क है। पुस्तक एक स्थायी चीज़ होती है जबकि पत्रिका में निरंतरता और गतिशीलता होती है। उसी तरह पत्रिका आर्डिनेरी जर्नल होती है जबकि शोध पत्रिका एक रिसर्च जर्नल होती है। मेरा प्रश्न यह है कि कल आपने स्वयं यह बात मानी थी कि हिन्दुस्तान में केवल दो फीसदी लोग अंग्रेजी जानते हैं इसलिए यदि हम कम्प्यूटर को जनजीवन से जोड़ना चाहते हैं तो हमें भारतीय भाषाओं को कम्प्यूटर नेटवर्क पर लाना होगा। मेरा आपसे यह कहना है कि हिन्दी में शोध पत्रिका का प्रकाशन इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा। इसलिए क्या आप हिन्दी में शोध पत्रिका के प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे? पुस्तकों के प्रकाशन से या पत्रिकाओं के प्रकाशन से यह मसला हल नहीं होगा और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। शोध पत्रिका के प्रकाशन का कोई निश्चित प्रस्ताव आपके पास है या नहीं, यदि नहीं है तो क्या लाएंगे? यह मेरा सवाल है।

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, J entirely agree that the answer which has been given is a little more general and it does not specifically state what the position in regard to research journals is. The position as it happens to be is that we do not have research journals, as we understand, in Hindi. We have gone into it and we would like to have research journals also started in Hindi and probably in other languages, wherever it is possible. When they could do it in Chinese, Japanese, German and so on, there is absolutely no reason why we should not be able to do it in our languages today. There is a question of terminology, but we could always use English words until the terminology, the equivalent terminology, comes into complete usage and this can be done. All I have to say is that those countries where we have research journals, they do also have research of a very high order on a very wide' scale. What is possible in India now is that whatever research we are doing, it will be contained in. the research journals, but at the same time our research base being not very wide, we will have to be take material from other journals in other languages from other countries and also the information in regard to research on a particular subject being carried out in other countries. And it, cannot be an omnibus journal, it has to be a specialised journal. If it is medical, it has to be medical; if it is educational, it has to be educational, etc. because research *in* such a big basket that we cannot have all the subjects contained in one basket. Therefore, this is a very wide programme. I would certainly like to make some begtnn- . ing at the earliest and I would like

to assure the Members that this lacuna has been realised, we have found *it* and we would like to remove it as quickly as possible.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, बहुत ही आश्वस्त करने वाला उत्तर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं । एक ही बात, जहां से उन्होंने अपना जवाब समाप्त किया, वहीं से मैं दूसरा प्रश्न प्रारम्भ करती हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विज्ञान और अनुसंधान परिषद गणित और भौतिकी में अपना प्रकाशन कर रही है, केवल थोड़ा सा और अनुदान दिये जाने पर वह इलेक्ट्रानिकी और कम्प्यूटर पर भी शोध पत्रिका प्रकाशित कर सकती है। तो केवल थोड़ा सा और अनुदान दे कर इस तरह की शोध प्रकाशित करवाने पर आप क्या विचार करेंगे ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, we will tell the University Grants Commission to pay special attention to this aspect.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, सदस्या बहिन सुषमा जी ने प्रधान मंत्री जी को दी बातों पर जो बधाई दी उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूं, कल की बैठक के लिए भी और शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन का विचार करने लिए भी। प्रधान मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि शोध पत्रिकाएं तो तब निकलेंगी जिसमें शोध होगा, बिना शोध के खाली शोध पत्रिकाएं नहीं निकल सकती हैं, इसलिए शोध होना चाहिए और कुछ शोध के लिए मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । प्राचीन हिंदुस्तान ने दुनिया को ज्ञान-विज्ञान दिया है और अब हम सब जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम दुनिया के सारे गणयंत्रों, कंप्यूटर्स को एक भाषा दे सकते हैं । समस्या यह है कि जो संस्कृत जानता है वह गणयंत्र, कंप्यूटर को नहीं जानता है और जो कंप्यूटर जानता है वह संस्कृत को कम जानता है और इसके कारण इसमें आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है । क्या इस दृष्टि से विभिन्न जो पत्रिकाएं होंगी उसमें केवल हिंदुस्तान की शोध पत्रिकाओं पर ही नहीं बल्कि संस्कृत और गणयंत्रों को इकट्ठा करने वाली शोध पत्रिकाओं पर भी क्या सरकार विचार करेगी, यह मेरे प्रश्न का एक हिस्सा है ।

दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का यह होगा कि ये जो नगद पुरस्कार हैं वह बहुत कम हैं क्योंकि 15 हजार रुपये किसी पुस्तक पर पुरस्कार हो तो मुझे लगता है कि यह उसके कवर पेज की भी कीमत नहीं होगी । तो क्या इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

तीसरा, सभापति जी से मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि यह जो "ख" और "ग" आदि इकट्ठा करने की पद्धति है यह अच्छा नहीं है । अगर "क", "क", "ख" और "ग" पूछा है तो उत्तर भी "क", "ख" और "ग" होना चाहिए । मंत्रालय चाहे सबको इकट्ठा करे लेकिन यह अच्छा नहीं है ।

मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने बहिन सुषमा जी को जैसे संतोष दिया है वैसे मुझे भी देंगे ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : श्रीमन्, बात ऐसी है कि पहले तो हमारा शोध शुरू हो जाए, बड़े पैमाने पर हो जाए । तो उसमें से हम शोध पत्रिकाएं निकाल सकेंगे, ला सकेंगे और उसमें जितनी कुछ इन्फार्मेशन चाहिए वह सब हम दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि यह जो पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार की राशि के बारे में मैं इससे पहले ही कह चुका हूं कि यह राशि कोई ऐसी नहीं है जिसको हम बड़े गर्व के साथ कहीं कह सकें कि यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इसमें कुछ बढ़ोत्तरी करने की अवश्य कोशिश की जाएगी ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, our hon. Member has enquired about the proposal for publishing research journals on electronics and

others in the Hindi language. The hon. Member is very much concerned about the advanced areas of electronics, etc. I would like to inform the Prime Minister that there is a strong feeling in the South that the Central Government is developing only one language. It is true. If we go through the annual reports of all Ministries we will find a chapter describing about the actions taken or proposed to be taken to develop the Hindi language. But at the same time we do not find a single sentence about the development of other Indian languages. Therefore', I would like to know from the hon. Prime Minister whether there is any proposal with. the Government of India *to* develop other Indian languages in the same way as it has done for the development of the Hindi language. It is a very important question. The unity and integrity of the nation lies in this question.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO. Sir, there is an institution called "Telugu. Academy" in Andhra Pradesh. I am not saying that it is unique. There may be similar institutions in other States in other language groups. But, if the work of the Telugu Academy for the last twenty years is examined you will find that the Academy has done everything that needs to be done, both on the technical side and the humanity side, in the Telugu language. We did have to face any number of obstacles in the beginning. There was apathy; there was lethargy; all these things were there, but we were able to push through the programme in a very successful manner and, I am sure, in Marathi and ether languages also this is being "lone and, I am equally sure, that in Tamil the work is no less. So the development of Indian languages initiated by the Central Government by paying Rs. 1 crore to start with for each language group has gone on so well in certain languages, not so well in other languages, I must admit. But this programme has been very successful and to say that the other languages have not developed at all, I would say, is not only an exaggeration, it is also far from truth.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am not satisfied with the answer. I have specifically asked about the working of the Central Government here in Delhi. We cannot find a single sentence about developing regional languages.

MR. CHAIRMAN: They have given Rs. 1 crore to each language. The State Government in Andhra Pradesh took the initiative when he was the Chief Minister and it is doing so well. The other Chief Ministers can also do the same.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We are asking for equal treatment of the other Indian languages on a par with Hindi. What they have done for Hindi, they have not done for other languages. The State Governments are saying that Rs. 1 crore is not sufficient.....

MR. CHAIRMAN: Dr. Ratnakar Pandey.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am not satisfied with the answer. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN; PIlase sit down. I have called Dr. Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महामहिम सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने कल जो कंप्यूटर के संदर्भ में मीटिंग की थी, उसमें मुझे बुलाया था, लेकिन अपनी मूर्खता और लापरवाही के कारण मैं उसमें पहुंच नहीं पाया । उसके लिए मैं ... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : पहली बार महसूस हुआ ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्योंकि इतना बड़ा अवसर प्रधान मंत्री जी ने दिया कि सारे सांसद जो इसमें रुचि रखते हैं, वह आयें और उनके साथ बैठ कर, कैसे भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर में प्रयोग हो, इसमें आपने रुचि ली, इसके लिये हम आपको भारतीय भाषाओं और हिंदी

ंत की ओर से बधाई देते हैं और अब मैं प्रार्थना यह कर रहा हूं कि जो आपका इलैक्ट्रानिक स्पेस और जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग हैं, इन तीनों की जो हिंदी संसदीय राजभाषा एडवाइजरी समिति है मैं उसका फाऊंडर मैम्बर हूं और मुझे यह कहने में खुशी है कि सन् 1984 में इन संस्थाओं ने काम करना शुरु किया। परमाणु ऊर्जा और स्पेस सेंटर इलैक्ट्रानिक से बढ़ कर के तकनीकी शब्द, जिसकी टेक्नीकलिटी की बात होती है, भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए कहां नहीं हैं और जितना सुंदर प्राइवेट लोगों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में टेक्नीकल लिट्रेचर निकाला हैं, उसको क्या आदर्श मान कर के विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालय के टेक्नीकलटी का बहाना बना करके उसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग हम नहीं कर सकते, एक बहाना बनाते हैं और उधर मंत्रालय की ओर से दस, बीस या पच्चीस हजार रुपये का पुरस्कार प्रति वर्ष आप कमवर्सिंग करते और किताब छापते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : : आप प्रश्न कर लें।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी के स्थान पर कंप्यूटरों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रचलन में जब आपने रूचि ली है, तो क्या कोई टाईम-बाऊंड फ्रेमवर्क उस पर लगा रहे हैं और कब तक उसको लगा देंगे ? और जो टैक्नीकैलिटी को बहाना बना कर राजभाषा की उपेक्षा करने की भारत सरकार ने आदत बना ली है, उसको खत्म करके एक आदर्श मान करके इन तीन मंत्रालयों का उसी आधार पर काम शुरु करायेंगे, यह मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

SHRIMATI MARGARET ALVA: We have a programme for introduction. ..

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, मुझे आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करनी है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है कि मेरे प्रश्न का जवाब वह न दें। मैंने कल की मीटिंग में अपनी लापरवाही और अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांग ली है और उसके बाद भी मेरे प्रश्न का जवाब प्रधान मंत्री जी न दें, यह थोड़ा मेरी गरिमा के . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अब यह तो मुश्किल हो जाएगा। यदि हरेक कहे कि मेरा जवाब प्रधान मंत्री दें, तो मुश्किल हो जाएगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इन विशेष परिस्थितियों में मैं ही जवाब दे रहा हूं।

श्रीमन्, यह भाषा ऐसी चीज है जिसको हुक्म देकर हम चला नहीं सकते हैं। समयबद्ध बहुत ठीक है. . . . . . लेकिन कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होते-होते होते हैं। एकदम हमारे कहने से कि अमुक समय तक यह होना ही चाहिए, यह संभव नहीं होता और भाषा का भी यही है। हमारा यह अनुभव रहा है भाषा के क्षेत्र में काम करते-करते कि हमें किसी भी चीज़ की तेजी को और बढ़ाने की कृत्रिम कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे असर उलटा पड़ता है। अभी कंप्यूटरों की बात ले लें। हमारे यहां लोगों की समझ में एक यह बात आ गई थी कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो या तो बहुत बड़े धनवान लोगों की चीज़ है या फिर ऐसे लोग, जो हमारे अवाम से, जनसाधारण से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनके इस्तेमाल की चीज़ है। अभी तक लोगों की समझ में यह नहीं आया है कि कम्प्यूटर एक टूल है, आपके विद्यार्थी के हाथ में जैसे लॉगरिथम टेबल होता है, आज कंप्यूटर या कैलकुलेटर हो तो उसको कितनी सुविधा हो सकती है, यह लोगों की समझ में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एक तरह से उसके जिम्मेवार हम भी हैं। जहां कंप्यूटर की बात आई राजनीतिक भाषा में हम यह कहने लग गए कि यह तो ऐसे लोगों का काम है, यह ऐसे लोगों की बात है, यह हाई-

लोग हैं, यह बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो एक तरह से इसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसलिए इसका प्रायश्चित हमें भी करना पड़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं मुझे करना पड़ेगा, पाण्डेय जी को करना पड़ेगा, सारे पक्षों के नेताओं को करना पड़ेगा, तभी यह बात, कंप्यूटर लोगों तक पहुंच सकता है । उसकी पहुंच ही जहां नहीं है, उसकी एक्सैप्टिबिलिटी ही नहीं है, लोग समझते हैं कि इसे हमें छूना नहीं चाहिए और उसमें ऐसी एक मिस्ट्री हो गई है, डिमिस्टीफिकेशन की पहले जरूरत है कि यह क्या है, यह कैसी चीज है, इसमें कोई ऐसा राज होगा जिसे हम नहीं जानते होंगे, यह कोई बड़ा परम रहस्य होगा। जब तक यह बात नहीं निकल जाती कंप्यूटर को हम मामूली संयंत्र के रूप में लोगों के सामने नहीं पेश करेंगे और उनकी फैमिलियरिटी उस से नहीं हो जाएगी, परिचय उससे नहीं होगा, तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ेगा और भाषाओं के बारे में बहुत कुछ काम भी तो करना है। अंग्रेजी में जो सुविधा है जैसे वर्ड प्रोसैसिंग की सुविधा है, डी-बेस की सुविधा है, सभी सुविधाएं हैं, आज वर्ड प्रोसैसिंग को ले लीजिए, आपके सारे कमांड्ज अंग्रेजी में आते हैं, हिन्दी में वर्ड प्रोसैसिंग होता है, तेलुगु में वही वर्ड प्रोसैसिंग होता है, लेकिन उस पर कोई किताब नहीं लिखी गई। आपको तो सैंकड़ों पुस्तकों के लिखने और लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संकल्प हमारा बिल्कुल ठीक है, यह हमको करके रहना है, लेकिन इसमें समय लगेगा और जब संकल्प ठीक है और सही दिशा में हम जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी करके उसको उलटना नहीं चाहिए। उसको धीरे-धीरे गति देने की कोशिश करनी चाहिए। यही सरकार करना चाहती है।

श्री मोहम्मद सलीम : माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने, जो जवाब यहां दिया गया, उसके बारे में हमें रोशनी डाली और मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो प्रश्न था उसमें रिसर्च जर्नल के बारे में, शोध पत्रिका के बारे में ही था, उसमें बढ़ करके ऊंचे दर्जे में हिन्दी में किताबें लिखने के बारे में यह जवाब में आ गया, जो प्रश्न में नहीं था वह भी आ गया। हम शोध पत्रिका के बारे में बात नहीं कर सकते, अगर हाई स्टैंडर्ड उस जबान में, भाषा में किताब नहीं रहेगी । तो मैं यह आग्रह करूंगा कि यहां जो लिखी है कि फिजिक्स कैमिस्ट्री, लाईफ साईंस, इंजीनियरिंग साईंस में यह दिया गया है कि उसमें ऊंचे दर्जे की किताबें लिखी जाएं और उसके लिए रिवार्ड भी दिया जाएगा, उसमें कंप्यूटर साईंस भी जोड़ लेना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी कंप्यूटर साईंस में रूचि रखते हैं, कंप्यूटर जो सापटवेयर हैं, उसे भारतीय भाषा में डिवैलप करने के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसैसिंग के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा तो उत्साह देने के लिए ऐसी स्कीम लागू करेंगे साईंस एंड टैक्नोलोजी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सापटवेयर की भारतीय भाषा में बरना हम जनता के पास कंप्यूटर को नहीं ले जा पायेंगे। मेरी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वह जो उत्तर यहां पर आया है हिन्दी भाषा में इस किताब को बढ़ावा देने के लिए; लिखने के लिए जो स्कीम लागू किया गया हैं भारतीय अन्य भाषाओं में भी विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान जो है इसकी चर्चा के लिए, उत्साह देने के लिए कोई स्कीम लागू करेंगे, खास करके जो स्टेट में यह काम कर रहे हैं, वह लोग जो वहां काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसे कोई अनुदान देने का बंदोबस्त करेंगे ताकि ऊंचे दर्जे की किताबें लिखी जाएं । कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर युनिवर्सिटी, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अपनी जबानों में वहां विज्ञान की चर्चा की एक धारा रही है, जिससे आचार्य जगदीश चन्द्र बसु, प्रफुल्ल चन्द्र राय—ये जुड़े हुए हैं। जैसे इलाहाबाद युनिवर्सिटी को हुए हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अनुदान दिया जाएगा हिंदी के लिए; उसके साथ-साथ मैं कहूंगा कि रीजनल यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ अनुदान का बंदोबस्त किया जाए ताकि वह अपनी भाषा में भी विज्ञान की चर्चा कर सकें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव: मैंने जब इलाहाबाद की बात कही तो कोई खास इलाहाबाद से पक्षपात करने के लिए नहीं कही। बात यह है कि जहां कहीं विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान मिलता है, उसमें इस बात के लिए खास ध्यान देना चाहिए, हम यह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को सुझाएंगे और जहां कहीं ऐसा सुझाव आएगा, ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो उनको अनुदान देने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और बराबर अनुदान दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अनुदान दिया जा रहा है, मेरा ऐसा विश्वास है, लेकिन फिर भी हम इसको डबल चैक करते हैं और उसको बताते हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, कंप्यूटर जहां तक मुझे ज्ञान है, एक डिसीप्लिन्ड स्लेव यानी अनुशासित गुलाम है और मालिक के हुकुम के अनुसार जो भी फीड किया जाता है वही देता है और इसकी शुरूआत सबसे पहले...

श्री सभापति: अब सवाल कर लो, इतिहास बताओगे तो समय निकल जाएगा, 45 मिनिट हो चुके हैं।

श्री सुरेन्द्रजी: सिंह अहलुवालिया : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं, कंप्यूटर से हम विदेश से तकनीक ला रहे हैं, पर कंप्यूटर की तकनीक की सृष्टि भारत में हुई थी। हजारों वर्ष पहले "लीलावती" नाम की एक पुस्तक छपी थी, आप जानते होंगे, जिसमें कंप्यूटर का सारा डिजाइन दिया गया था। आज वह किताब भारत में उपलब्ध नहीं है। हॉलैंड में, जापान में, अमेरिका में उसका उनकी भाषा में संस्कृत से अनुवाद कर कर के वह पुस्तक वहां मिलती है, पर भारत में उपलब्ध नहीं है। क्या प्रधान मंत्री महोदय "लीलावती" को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर के या यहां की रीजनल लैंग्वेजेज में अनुवाद कर के यहां टैक्नीशियनों को उपलब्ध कराएंगे?

श्री पी. वी. नरसिंह राव: जहां तक मुझे स्मरण है "लीलावती" यहां भी उपलब्ध थी क्योंकि हमने उसके बारे में सुना था। जब हम विद्यार्थी थे, "लीलावती" के बारे में हमने सुना था और कुछ पंडित ऐसे थे जिन्होंने "लीलावती" का अध्ययन किया था। अब मुझे नहीं पता कि इन दिनों में जब हम बहुत ज्यादा मुहज्जिब हो गए तो पुरानी किताबें लुप्त हो गयी हैं और दूसरी जगह जाकर उनको ढूंढना पड़ता है। अगर ढूंढना हो तो वह भी हम करेंगे। यह हम जानते हैं कि हमारे कई संस्कृत के महान ग्रंथ यहां से लुप्त हो गए हैं और उनका अनुवाद तिब्बत में मिलता है। वहां से फिर हम को वापिस लाने की नौबत आई है। तो यह हुआ है। हमारी मीडिबल शताब्दियों में यह सारी चीज हुई है, लेकिन "लीलावती" के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि वह यहां उपलब्ध थी कोई 50 साल पहले जब हम पढ़ते थे और अब भी है तो ठीक है, फिर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बाहर से लाने की कोशिश करनी होगी। यह हम जरूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Up-endra.

SHRI P. UPENDRA; Sir, the Prime Minister is a great scholar, not only in one language but also in several languages... *(Interruptions)* ..

MR. CHAIRMAN: I am very happy that one Telugu man is praising another Telugu man!. ..*(Interruptions)*...

SHRI P. UPENDRA; Not that, Sir. He mentioned about the Telugu Academy and that is why I said it. -But, Sir, he should be equally interested in the development of all the languages.

MR. CHAIRMAN: He was associated with the Telugu Academy.

SHRI P. UPENDRA: But that is not enough. The State-level Academies are not enough. There should be some other Central agency. The

Sahltya Akademi is there, but its scope is very limited. Not only is there a need for the development of these languages, but there is also the need for translation of great works, from one language to another. What I would suggest is that just as there are Hindi directories in various Ministries, there should be a separate department for the development of Indian languages in the HRD Ministry. Therefore, will he consider setting up a separate department for the development of the Indian languages in the Human Resource Deve-, lopment Ministry? There are five Departments and I think he can add one more department to the Ministry for the development of the other Indian launguages. Will he kindly consider this?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I cannot answer this off-hand because there are some implications in this. The responsibility, the main responsibility, of developing the regional languages, other languages, would naturally lie on the State Governments and expertise is available there.

SHRI P. UPENDRA: What about co-ordination from the Centre?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Yes, we can consider that. But I have to look into it and see whether it is not being done. I will have to look into it. But, mainly it is the areas— I am not even talking about the Governments—I am talking of the areas where the language is a live language, it is spoken, it is growing, it is getting into the lives of the people, reflecting the lives and sentiments of the people, it is in those areas that it could be really developed. What we can do from here in order to encourage that process, that we can always see. If there is any inadequancy in it, w*e* can certainly make it adequate.

MR. CHAIRMAN: Question No. 245. '

रसायनों का निर्यात

***†245. श्री रणजीत सिंह :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बिग पोटेंशियल फॉर बूस्टिंग केमिकल एक्सपोर्ट स्टडी' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया" द्वारा गठित अध्ययन-दल की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रसायनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कोई योजना नहीं बनायी गई है, तो उसके क्या कारण हैं?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (f) Yes, Sir. The new trade policy announced by the Government recently, which has brought about major reforms in the Exim Strip System and Advance Licensing, has been formulated after taking into account the various suggestions received from the trade and industry and the recommendations of such study reports.

SHRI RANJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir. although the Minister has replied, still some portion needed clarification.

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Ranjit Singh.